(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाड़ी): (क) और (ख) पिछले छः महीनों के दौरान प्राप्त हुई ज़ोन-वार शिकायतें इस प्रकार हैं:

रेलवे जोन	शिकायतों की संख्या
मध्य	70
पूर्व	15
उत्तर	35
पूर्वोत्तर	23
पूर्वोत्तर सीमा	-
दक्षिण	05
दक्षिण-मध्य	14
दक्षिण-पूर्व	13
पश्चिम	28

(ग) और (घ): इस बुराई पर काबू पाने के लिए सर्तकता के लिए सर्तकता और वाणिज्यिक विभागों द्वारा स्टेशनों पर और चलती गाड़ियों में निवारक, अचानक और छद्म रूप से जांच की जाती है। इसके अलावा, ग्रीष्मकालीन भीड़-भाड़ के दौरान और पूजा की छुट्टियों में भी विशेष अभियान चलाये जाते हैं। जांच के दौरान दोषी पाये गये कर्मचारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कमजोर वर्गों के लिए आवास संबंधी योजना

1118. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले और समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करवाने हेतु कोई नई आवास योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० अहलुवालिया): (क) से (ग) जहां तक शहरी आवास का संबंध है, केन्द्र सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों अथवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास मुहैया कराने हेतु कोई नयी योजना आरम्भ नहीं की है।

तथापि, सरकार द्वारा हाल ही में शुरू प्रधानमंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम में एक आश्रय उन्नयन घटक भी है, जिसके तहत 50,000 से 1,00,000 तक की आबादी वाले कस्बों में गरीबी रेखा से नीचे के शहरी परिवारों (जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1991-92 के मूल्यों पर 11,850 रुपए से कम है तथा जिनके पास भूमिधरी प्राप्त है) को, 2500 रुपए की अधिकतम सीमा तक मकान के नवीकरण/मरम्मत लागत के 25 प्रतिशत तक सरकारी इमदाद देने की व्यवस्था है। यह योजना उन सभी राज्यों में लागू कर दी गयी है, जहां पालिका निकायों के चुनाव हो चुके हैं। कार्यक्रम के इस भाग को चलाने के लिए राज्य-वार नियत राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

विवरण

प्रधान मंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम (पी एम आई यू पी ई पी) 1995-96 (आश्रय उन्नयन घटक) के कार्यान्वयन के लिए नियत राज्य-वार राशि:

(रुपए लाख में)

क्र०सं०	राज्य	नियत राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	92.35
2.	असम	11.30
3.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	3.47
4.	बिहार	77.17
5.	गुजरात	54.96
6.	गोवा	8.48
7.	हरियाणा	17.24
8.	कर्नाटक	59.76
9.	केरल	24.79
10.	मध्य प्रदेश	72.79

1	2	3
11.	महाराष्ट्र	89.34
12.	उड़ीसा	25.35
13.	पंजाब	28.85
14.	राजस्थान	47.67
15.	तमिलनाडु	98.54
16.	उत्तर प्रदेश	142.83
17.	पश्चिम बंगाल	64.00
18.	नागालैंड	5.65
19.	पांडिचेरी	2.84

MOUs for setting up industries in Punjab

1119. SHRI IQBAL SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the number of private parties that have signed the Memorandum of Understanding with Government to set up industries in the State of Punjab?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (Dr. C. SILVERA): With the commencement of new Industrial Policy in August, 1991, for all the delicensed industries, an entrepreneur has to file an Industrial Entrepreneur Memoranda (IEM) with the Government.

Since the commencement of New Industrial Policy in August, 91 till October, 95, 1207 Industrial Entrepreneur Memoranda (IEMs) have been filed by entrepreneurs in private & public sectors for establishing new units/ new articles/expansion of existing industrial units etc. in the State of Punjab.

Konkan Railway Project

1120. SHRI VAYALAR RAVI:
SHRI B. K. HARIPRASAD:
Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the present status of the Konkan Railway project and whether the work is going on according to schedule;

(b) what is the likely date of completion/commissioning and whether the entire stretch will be commissioned in one go or in phases; and

(c) whether Mangalore will be upgraded as the terminal point of Konkan Railway with new facilities like expanded loco and car sheds and what are the other facilities which Railways plan to make for places of pilgrimages/ tourist attractions like Udupi/Malpe etc. on the coast.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) The Weighted physical progress of the project upto date is about 92%. The work is going on according to the revised schedule of completion.

(b) The project is slated for completion by March, 1996. The project is being commissioned in phases. Train services have been introduced on Roha-Khed and Mangalore-Kundapura sections.

(c) No, Sir. There is no such proposal.

Delay in Japanese city project in Gurgaon

1121. SHRI K.R. MALKANI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the projected 'Japanese City' in Gurgaon, Haryana, has run up against high land acquisition prices as reported in the Statesman dated 19th November, 1995;

(b) the reasons for which the project has taken 16 years to take off; and

(c) whether Government would advise Japanese industry to choose a less expensive site farther away from a major urban centre?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) There has been an on-going dialogue between the Government of Haryana and the Consortium of Japanese Companies on the implementation of Industrial Model Town at Gurgaon. There could have been some differences in perception between the State Government of Haryana and the Consortium of Japanese Companies over certain issues including the prices of land. However the matter is getting attention from both sides for a possible settlement.